खनन सुधारों पर उत्तराखंड को मिला 100 करोड़ का प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को को माइनर मिनरल रिफार्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 100 करोड़ की राशि प्रदान की है। उत्तराखंड ने इसमें सात रिफार्म में से छह रिफार्म में कार्य कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले केंद्र एसएमआरआइ (स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स) रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर चुका है। खनन सुधारों पर राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर केंद्र ने प्रोत्साहन राशि के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड ने दो श्रेणियों में अपना स्थान बनाया है।

खनन क्षेत्र...

ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में शामिल राज्यों- नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। सरकार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अवैध खनन पर लगाम कस रही है। जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं।

...तो परिणाम मिलते ही हैं

जब काम दमदार हो और नीयत साफ हो...तो परिणाम मिलते ही हैं। खनन के क्षेत्र में पीएसडी सरकार के सुधारात्मक प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं। पहले के वर्षों में खनन से जितना राजस्व आता था, अब इस सरकार में उतने के तो केवल पुरस्कार ही लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और अवैध खनन व चोरी पर रोक के चलते खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में जबरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है। पहले के 400-500 करोड़ रुपये के मुकाबले बीते साल में खनन से 1100 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई है। सूत्रों के अनुसार, विशेषकर खनन को लेकर राज्य के कुछ चुनिंदा विघ्नसंतोषी लोग हमेशा एक नकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं जबकि ऐसे विघ्नसंतोषी लोगों की सरकारों में राजस्व रसातल में रहता था और अवैध कारोबार अपने चरम पर। मुख्यमंत्री धामी ने बीते वर्षों में अपने कड़े कदमों से यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश के तमाम विभाग केवल कमाने-खाने का जरिया भर नहीं हैं, बल्कि इन विभागों की व्यवस्थाओं और तमाम प्रक्रियाओं में सुधार करके राज्यहित में कितना महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसे राज्य में जहां पर राजस्व प्राप्ति के स्रोत कम हों, वहां अपने 'जीरो लीकेज' के संकल्प के बूते पहले तो राजस्व में गुणात्मक वृद्धि करना, फिर सैकड़ों करोड़ के पुरस्कार केंद्र से लेकर आना, राज्य के नेतृत्व के प्रबंधन और दूरदर्शिता को दर्शाता है।